

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Nainital (U.K.)

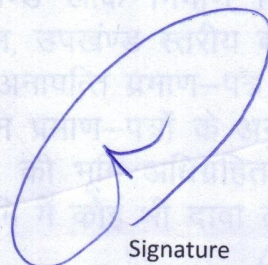
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated 25/11/14. at timeat Nainital in which application claiming rights in rang / area measuring 0.4212 hect for the Construction of **Bareilly-Almora M/Road to Sirsa** Motor Road (1.75 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Dated: 25/11/14



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-Nainital

No---

Dated-25/11/14

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.9212 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Kathgodam (Nainital) (name of user agency) for Construction of **Bareilly-Almora M/Road to Sirsa Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of **Sirsa village in Kushyakutoli tehsil**.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9212 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

नैनीताल

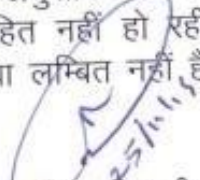
प्रपत्र-23

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग में सिरसा तक मोटर मार्ग का निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग में सिरसा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9212 हैक्टेयर बनभूमि प्रयोक्ता एजेंसी पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति, कुश्याकुटौली तथा संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं । बन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है । परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली बन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है ।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल


जिलाधिकारी,
नैनीताल

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

क्षेत्र - 30.30

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - सिरसा
तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सिरसा क्षेत्र में सिरसा निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (.....हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि.....हे०, वन पंचायत भूमि.....हे०) अर्थात् कुल ०.१२१२ हे० वन भूमि का सिविल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिरसा द्वारा दिनांक १६/१०/१४ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिरसा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.१२१२ हे० प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/- Prishankumar
ग्राम पंचायत सिरसा अधिकारी
ग्राम सिरसा
(नैनीताल)

ह०/- रणजीत सिंह
ग्राम प्रधान,
सिरसा

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1/प्रान्त-304

दिनांक 16/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत... सिरसा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहनराज	मोहनराज
2-	गोपाल कल	गोपाल कल
3-	जलम सिंह	जलम सिंह
4	बालम सिंह	बालम सिंह
5	किशोर आर्य सिंह जीना	किशोर आर्य सिंह
6	कोटल सिंह जीना	कोटल सिंह
7	राजेश सिंह जीना	राजेश सिंह
8	रामेश सिंह	रामेश सिंह
9-	रमेश सिंह जीना	रमेश सिंह
10-	रमेश सिंह जीना	रमेश सिंह
11.	रमेश सिंह जीना	रमेश सिंह
12-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
13	मोहन सिंह	मोहन सिंह
14.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
15	मोहन सिंह	मोहन सिंह
16	मोहन सिंह	मोहन सिंह
17-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
18	मोहन सिंह	मोहन सिंह
19	मोहन सिंह	मोहन सिंह
20-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
21	मोहन सिंह	मोहन सिंह

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम-

4/10/20

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति - राप्रक

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 0.9212 हे० आरक्षित वन भूमि (0.9212 हे० आरक्षित वन भूमि) का सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि हे० अर्थात् कुल 0.9212 हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील नैनीताल) की दिनांक 21/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री च. पी. सिंह उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री च. पी. सिंह उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2. श्री बिनकर नेवासी उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3. श्री सुभाष पांडे सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4. श्री हरि सिंह बी.डी.सी क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों की अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 0.9212 हे० वन भूमि (0.9212 हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत

-2-

परियोजना के निर्माण हेतु 0.92.12 हे० वनभूमि मा. जिला प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील- उज्जैन
जनपद- नैनीताल

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील-
जनपद- नैनीताल।